

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अधिशाली अधिकारी,
नगर पालिका परिषद-रानीखेत, शिवालिक नगर,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक: 20 अप्रैल, 2017

विषय:- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों पर सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के कम में समस्त नव सृजित नगर पालिका परिषदों को वित्तीय वर्ष 2017-18 की प्रथम छमाही किशत हेतु धनराशि का संकमण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों पर सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के कम नव सृजित नगर पालिका परिषदों को संलग्न विवरणानुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 की प्रथम छमाही किशत हेतु कुल ₹1,25,00,000.00 (₹ एक करोड़ पच्चीस लाख मात्र) की धनराशि संकमित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संकमित की जा रही है:-

1. संकमित धनराशि का उपयोग शासनादेश सं0-316/XXVII(1)/2017, दिनांक: 31 मार्च, 2017 द्वारा निर्गत मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अन्तर्गत किया जायेगा। इस धनराशि से किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।
2. आयोग की संस्तुतियों के कम में शहरी स्थानीय निकायों को संकमित की जा रही धनराशि का उपयोग सर्वप्रथम निकायों के स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत समस्त प्रकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते आदि तथा पथ प्रकाश व जल संस्थान के देयकों के भुगतान पर किया जायेगा।
3. संकमित धनराशि से वाहन आदि कय नहीं किया जायेगा। यदि कार्यहित में कोई वाहन कय करना आवश्यक हो तो इस सम्बन्ध में शासन स्तर की अनुमति आवश्यक होगी। धनराशि बचनबद्ध मदों में व्यय की जायेगी।
4. संकमित की जा रही धनराशि कोषागार से आहरित करने के लिये बिल सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।
5. आयोग द्वारा किसी भी शहरी स्थानीय निकाय को तब तक कोई धनराशि अन्तरित नहीं किये जाने की संस्तुति की है, जब तक निदेशक, लेखा परीक्षा या उसके द्वारा नामित किसी अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित न कर दिया जाय कि पेंशन निधि हेतु अंशदान तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के दावों का भुगतान निकाय द्वारा कर दिया गया है। द्वितीय वर्ष अर्थात् वर्ष 2018-19 की द्वितीय किशत तब तक अवमुक्त नहीं की जायेगी जब तक निदेशक, लेखा परीक्षा से पिछले वर्ष के लिये प्रमाण-पत्र प्राप्त न कर लिया जाय।
6. शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागीय अधिकारी/ वित्त नियंत्रक / वरिष्ठ लेखा अधिकारी/ सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में कोई विचलन हो तो वित्त नियंत्रक/ विभागीय अधिकारी इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल वित्त विभाग को दी जायेगी। वित्त विभाग की पूर्व अनुमति के बिना कोई विचलन मान्य नहीं होगा। इस धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र सम्बन्धित निकायों, के अध्यक्ष से प्रतिहस्ताक्षरित करा कर वित्त आयोग निदेशालय, कमरा न0-223, द्वितीय तल, विश्वकर्मा भवन, सचिवालय, देहरादून को कार्यों के विवरण के साथ उपलब्ध कराया जायेगा तदोपरान्त ही अगली किशत अवमुक्त की जायेगी।
7. नव सृजित नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2017-18 में ₹1.00 करोड़ विशिष्ट सहायक अनुदान एवं ₹25.00 लाख विशेष सहायक अनुदान के रूप में कुल ₹1.25 करोड़ की धनराशि दो किशतों में अंतरित की जायेगी, जिसमें से ₹25.00 लाख की धनराशि उन मदों पर व्यय की जायेगी जो मुख्य रूप से पूंजीगत कार्य या राजस्व व्यय की प्रारम्भिक मदें हो

परन्तु इस अनुदान से कोई स्टाफ कार/ जीप कय नहीं की जा सकेगी। यह अपेक्षित है कि प्रथम वर्ष इन निकायों द्वारा अपना कार्यालय आदि स्थापित किया जायेगा और वर्ष 2018-19 से स्वयं का राजस्व अर्जित करना प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

8. निदेशक, शहरी विकास विभाग निकायों को अंतरित धनराशि के समय से उपयोग हेतु उत्तरदायी होंगे।
9. नगर विकास विभाग संकमित धनराशि के नियमानुसार उपयोग की समीक्षा करेंगे तथा इसके समुचित उपयोग के लिये उत्तरदायी होंगे। कोषागार से आहरित धनराशि की बाउचर संख्या तथा दिनांक की सूचना महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को भेजेंगे।
10. सम्बन्धित निकाय की अलोटमेन्ट आईडी संलग्न है।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के लेखा अनुदान की अनुदान संख्या-07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-आयोजनेतर-01-नगरीय स्थानीय निकाय-192-नगरपालिका/नगर निकाय-03 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करें से समनुदेशन-00-20-सहायक अनुदान/ अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

संलग्न:- यथोपरि।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव, वित्त।

संख्या:- 403 (1)/XXVII(1)/2017, तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- प्रमुख सचिव, शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ, उत्तराखण्ड।
- 4- सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 5- निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय, 43/6, माता मन्दिर मार्ग, धर्मपुर, देहरादून।
- 6- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 7- निदेशक, वित्त आयोग निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
- 8- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 9- शहरी विकास अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन।
- 10- एन0 आई0सी0 सचिवालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव, वित्त।

शासनादेश संख्या: 403 /XXVII(1)/2017

::देहरादून:: दिनांक: 20 अप्रैल, 2017

तुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के
कम में नव सृजित नगर पालिका परिषदों को वित्तीय वर्ष 2017-18 की
प्रथम छमाही किश्त हेतु धनराशि संकमण

(धनराशि हजार ₹ में)

जिला	क्र. सं.	स्थानीय निकाय का नाम	वित्तीय वर्ष 2017-18 की प्रथम छमाही किश्त हेतु देय संकमण
अल्मोड़ा	1	रानीखेत	6250
हरिद्वार	2	शिवालिक नगर	6250
योग			12500

(₹ एक करोड़ पच्चीस लाख मात्र)

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

बिभागाध्यक्ष का नाम - Secretary Finance**बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 2017-2018****अनुदान शंख्या 007 (वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवार्य)****लेखाशीर्षक- 3604 - स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन****01 - नगरीय स्थानीय निकाय****192 - नगर पालिका/नगर निकाय****03 - राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन****00 - राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन****NonPlan Voted**

S.No	Treasury	DDO Name	Allotment Id	Allotment Date	Previous Allotment	Current Allotment	Name of local bodies
1	0100-Dehradun	4183-District Magistrate (For Grants)Dehradun	H1704070689	19-APR-2017	0	129125000	
2	0100-Dehradun	4183-District Magistrate (For Grants)Dehradun	H1704070697	19-APR-2017	0	7006000	
3	3600-Nainital	4183-District Magistrate (For Grants)Nainital	H1704070691	19-APR-2017	0	77966000	
4	3700-Almora	4183-District Magistrate (For Grants)Almora	H1704070685	19-APR-2017	0	17518000	
5	3700-Almora	4183-District Magistrate (For Grants)Almora	H1704070725	19-APR-2017	0	6250000	
6	3800-Pithoragarh	4183-District Magistrate (For Grants)Pithoragarh	H1704070693	19-APR-2017	0	54422000	
7	3900-Narendra Nagar	4183-District Magistrate (For Grants)Narendra Nagar	H1704070694	19-APR-2017	0	10950000	
8	3900-Narendra Nagar	4183-District Magistrate (For Grants)Narendra Nagar	H1704070698	19-APR-2017	0	8403000	
9	4000-Gopeshwar	4183-District Magistrate (For Grants)Chamoli	H1704070687	19-APR-2017	0	50370000	
10	4100-Uttarkashi	4183-District Magistrate (For Grants)Uttarkashi	H1704070696	19-APR-2017	0	25372000	
11	4200-Garhwal	4183-District Magistrate (For Grants)Pauri	H1704070692	19-APR-2017	0	72671000	
12	6100-New Tehri	4183-District Magistrate (For Grants)Tehri	H1704070700	19-APR-2017	0	26474000	
13	6500-Haridwar	4183-District Magistrate (For Grants)Haridwar	H1704070726	19-APR-2017	0	6250000	
14	6500-Haridwar	4183-District Magistrate (For Grants)Haridwar	H1704070690	19-APR-2017	0	49628000	
15	7500-U S Nagar	4183-District Magistrate (For Grants)U S Nagar	H1704070695	19-APR-2017	0	113931000	
16	8800-Champawat	4183-District Magistrate (For Grants)Champawat	H1704070688	19-APR-2017	0	19652000	
17	8900-Bageshwar	4183-District Magistrate (For Grants)Bageswar	H1704070686	19-APR-2017	0	9547000	
18	9000-Rudraprayag	4183-District Magistrate (For Grants)Rudraprayag	H1704070699	19-APR-2017	0	10123000	
		Total:			0	695658000	

(अमित सिंह नेगी)
 सचिव, वित्त
 उत्तराखण्ड शासन